



04 - लोकतंत्र में पुनाव
आयोग एवं सराव के
अर्थ



05 - अंतिम दर्शन के कागज पर
पहुंचे हाथी

A Daily News Magazine

इंडॉर

मंगलवार, 12 अगस्त, 2025



वर्ष 10 अंक 303, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2

06 - एथेनाल प्लॉट सुताने से
बढ़ी मरका की मांग,
उत्पादन और माव बढ़ने...



07 - गोट की पवित्रता बचाने
के लिए प्रदेशभर में
पुलाल ढान और...

खबर

खबर

प्रसंगवाच

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटोकशन कानून पर क्यों उठरहे सवाल ?

मंग धोदार

सा

ल 2023 में भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटोकशन एकत्र पारित किया। यह कानून नामिकों के निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मक्सद से लाया गया था। कई मरकों पर विचार के बाद अगस्त 2023 में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ और इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। हालांकि, कानून के बनने के बाद से ही इसकी आलोचना हो रही है। आलोचकों में परकार भी शामिल हैं, जिनका मानना है कि इस कानून से पत्रकारिता की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

बीते 28 जुलाई को कई पत्रकार संगठनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआरटीवाई) के सचिव एवं कृष्ण से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने सरकार से कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन की मांग की। फिलहाल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटोकशन एकत्र लागू नहीं है। इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिन पर केंद्र सरकार को बैठक एवं संशोधन की आवश्यकता है, जिन पर अपनी विचार किया जा रहा है।

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजाता को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था, जिसके बाद यह कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी अफसर के व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल करता है, तो उसमें उस अफसर के निजी डेटा का जिक्र आ सकता है। इसलिए पत्रकारों ने इस कानून के कई प्रावधानों पर अपत्ति जारी है। जैसे कि इस कानून के तहत सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का डेटा साझा करने का आदेश दे सकती है। पत्रकारों को आशका है कि अगर सरकार इस तहत का आदेश जारी करती है, तो उसे कुछ सुन्दरी की व्यवस्था देनी होगी। मिसाल के तौर पर किसी डेटा लेने से पहले उस व्यक्ति से सहमति लेनी होगी, डेटा लेने से पहले कानून की सुरक्षा के लिए करना होगा और साथ

ही डेटा की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। इसके मुताबिक, कोई व्यक्ति अपना निजी डेटा देने के बाद उसे हटवाने की भी माँग कर सकता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार दोनों बादकर 500 करोड़ रुपये तक भी कर सकती है।

निजी डेटा में वह सारी जानकारी शामिल है जिससे किसी को वहचान सार्वजनिक हो सकती है। इसमें नाम, पता, फोन नंबर, तस्वीर, सेहत और वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारी और किसी व्यक्ति की इंसरेन्ट ब्राइजिंग हाईटी जैसे विवरण शामिल हैं। साथ ही, इस कानून में डेटा को 'प्रोसेस' करने की भी परिधि दी गई है। इसमें डेटा इकट्ठा करना, उसे स्टोर करना और वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारी के लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की सम्मा 'डेटा प्रोटोकशन बोर्ड ऑफ इंडिया' की होगी। यह बोर्ड जुर्माना लगाने, शिकायतों पर सुनवाई करने जैसे कई मामलों में काम करेगा।

पत्रकारों की माँग है कि पत्रकारिता के कारों के लिए इस कानून से छूट दी जानी चाहिए। वर्तमान में कुछ उद्देश्य, जैसे अपराध की जाँच के लिए डेटा प्रोटोकशन कानून से छूट दी गई है। जब इस कानून का पहला ड्राफ्ट साल 2018 में प्रकाशित हुआ था, तब उसमें पत्रकारिता से संबंधित कई प्रावधानों से छूट दी गई थी। इसी तरह साल 2021 के ड्राफ्ट बिल में भी पत्रकारिता के लिए कुछ छूट थी। हालांकि, साल 2023 में जब यह कानून प्रारंभित किया गया, तो पत्रकारिता से जुड़ी छूट दी गई। यह साथ नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया। पत्रकार संगठनों का कहना है कि 'पत्रकार की परिधाना' को केवल मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ने अपनी विद्वां में यह भी उल्लेख किया है कि योगेर और सिंगापुर जैसे देशों के डेटा प्रोटोकशन कानूनों से प्रभावित होते हैं। कई बार रिपोर्टिंग में ऐसे स्थान शामिल होते हैं जिनकी गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है।

फरवरी 2024 में 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' ने केंद्रीय मंत्री अधिकारी विष्णव नोंग चिंटी लिखकर इस कानून के कई प्रावधानों पर चिन्ता जताई थी। गिल्ड ने लिखा था कि यह कानून 'पत्रकारिता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है'। पत्रकारों का कहना था कि इस कानून से इंडिया और दूसरी जैजे प्रभावित न हो जाए लेकिन खाजी विद्वां पत्रकारिता और सर्वदानशील रिपोर्टिंग पर इसका असर पड़ सकता है। 25 जून को 22 प्रेस संगठनों और एक हजार से ज्यादा पत्रकारों ने भी सरकार को जापन भेजा, जिसमें कानून में बदलाव की माँग की गई थी। इन पत्रकारों में अखबार, टीवी, यूट्यूब और फ़िल्मी पत्रकार पत्रकारिता शामिल हैं।

पत्रकारों की माँग है कि पत्रकारिता के कारों के लिए इस कानून से छूट दी जाए चाहिए। वर्तमान में कुछ उद्देश्य, जैसे अपराध की जाँच के लिए डेटा प्रोटोकशन कानून से छूट दी गई है। जब इस कानून का पहला ड्राफ्ट साल 2018 में प्रकाशित हुआ था, तब उसमें पत्रकारिता से संबंधित कई प्रावधानों से छूट दी गई थी। इसी तरह साल 2021 के ड्राफ्ट बिल में भी पत्रकारिता के लिए कुछ छूट थी। हालांकि, साल 2023 में जब यह कानून प्रारंभित किया गया, तो पत्रकारिता से जुड़ी छूट दी गई। यह साथ नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया। पत्रकार संगठनों का कहना है कि 'पत्रकार की परिधाना' को केवल मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ने अपनी विद्वां में यह भी उल्लेख किया है कि योगेर और सिंगापुर जैसे देशों के डेटा प्रोटोकशन कानून से सुनिश्चित होनी जाती है।

30 जुलाई को एक प्रेस कानूनेस में एप्रेस कलब ऑफ इंडिया की उपायकारी पत्रकार संगीता बरुआ

पिशारोती ने बताया कि उन्होंने 28 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की थी। उनके अनुसार, 'सरकार को आरे से कहा गया है कि इस कानून से पत्रकारों को कोई मुश्किल नहीं होगी। मंत्रालय के सचिव ने हमें एप्रेस क्यूज़ (फ्रॉन्टलैंगी अस्कूल क्लैश्टर्स) तैयार करके देने का कहा है।'

सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई एक्ट) में प्रावधान है कि इसके तहत कई निजी जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन आर सावधानिक द्वितीय जानकारी को जापन नहीं करता है। यह प्रावधान बस इतना कहता है कि किसी को निजाता को ग़लत तरीके से पेश नहीं कर सकता। यह प्रावधान बस इतना कहता है कि जापन के लिए डेटा प्रोटोकशन कानून में संशोधन के बाद यह प्रावधान बस इतना कहता है कि जापन के लिए डेटा प्रोटोकशन कानून के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

सरकार का तर्क है कि यह कानून सुनील कोर्ट के उन निर्देशों के अधार पर तैयार किया गया है, जिनमें 'निजाता' को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए जिनजाता की सुरक्षा मुश्किल अवधारणा के लिए डेटा प्रोटोकशन कानून से छूट दी गई है। जब वर्तमान में कुछ उद्देश्य, जैसे अपराध की जाँच के लिए डेटा प्रोटोकशन कानून से छूट दी गई है। तब उसका अधिकारी विष्णव नामी अधिकारी विद्वां ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि डेटा प्रोटोकशन कानून से सुनिश्चित होनी जाती है।

विकास की गाड़ी कभी भी पर्यावरण की पटरी से नहीं उतरेगी

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि संभवतः यह पर्यावरण की पटरी जाती रहेगी। यह मध्यप्रदेश के सभी अभियांत्र और वर्चुअल मान्यता से एक साथ जुड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विशेष रूप से आभार मानते हुए कहा कि विकास की गाड़ी कभी भी पर्यावरण की पटरी से नहीं उतरेगी।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि संभवतः यह पर्यावरण की पटरी के लिए ड्राफ्ट बिल में विकास की गाड़ी को अवधारणा में भेजकर बेहतर करने का अध्यनयन कराया गया। विभाग ने उच्च गणकता से सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कारों में प्रयुक्त बिस्ट्रिम केवल सकारी रिफिलरियों से ही खोरीन्दे का निर्याय लिया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोकपथ मोबाइल एप के माध्यम से सड़क मरम्मत व्यवस्था को सुदूर किया गया है। पहले गाड़ों की अपराध करने के लिए निर्माण कारों में यह व्यापक बदलाव हो गया है। यह व्यापक बदलाव के लिए ड्राफ्ट बिल में विकास की गाड़ी को अवधारणा में भेजकर बेहतर करने का अध्यनयन कराया गया। विभाग ने उच्च गणकता से सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कारों में प्रयुक्त बिस्ट्रिम केवल सकारी रिफिलरियों से ही खोरीन्दे का निर्याय लिया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोकपथ मोबाइल एप के माध्यम से सड़क मरम्मत व्यवस्था को सुदूर किया गया है। पहले गाड़ों के लिए ड्राफ्ट बिल में विकास की गाड़ी को अवधारणा में भेजकर बेहतर करने का अध्यनयन कराया गया। यह व्य



इंदौर ■ मंगलवार, 12 अगस्त 2025

ताइवान को लेकर भारत पर क्यों भड़का चीन का ग्लोबल टाइम्स

बोला-इससे नहीं होने वाला कोई फायदा

बीजिंग (एजेंसी)। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान के साथ संबंधों को लेकर भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है कि ताइवान के मुद्रे को तुल देने से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चीन के साथ संबंधों को सुधारने पर भी जोर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर यह जहां ताइवान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की हो रही वकालत के जबाब में दिया है। विशेषज्ञों ने बिना चीन को भड़काए भारत-ताइवान संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। हालांकि, ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के रणनीतिक हलकों में यह आम राय है और इससे कोई लाभ नहीं होगा।



• ताइवान से मजबूत संबंधों की वकालत कर रखे विशेषज्ञ-ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि यह विवार नया नहीं है। इस तरह के सुआव पहले भी दिए जा चुके हैं। 19 मई को चीन में भारत के पूर्व राजदूत विजय गोखले ने ताइवान भारत के लिए वर्षों सहत पूर्णपांच होना चाहिए शीर्षक से एक लेख लिया था। उहोंने लिया, ताइवान जलद से जल्द सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों से कुते उड़ाए। जरूरत हो तो इसके लिए अलग बल बनाए दिरअसल, कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए यह मामला उठाया था, जब संघर्ष में पैश एक रिपोर्ट में दिली-एनसीआर में रीबीजे के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट बोला-दिली-एनसीआर में कृतों को पकड़कर नसबंदी करें, इन्हें शेल्टर होम में रखें, नहीं तो कार्रवाई

नईदिली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि आवारा कुतों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने कहा, इस काम में कोई दिलाई बर्दाशत नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया, तो उसके लिए एक सख्त कार्रवाई होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस राम रामदेवन की ओर से कहा कि दिली, एमसीआर और एनएसीआर के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा-लोग ईदगाह में बने मकबरे पर भगवा ढांडा और पूजा-लोग ईदगाह पहुंच गए।

पुलिस ने यहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिंगिंग कर दी थी, पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भढ़क गए। लेकिन लाठी-डंडे से लैस हिंदू संगठन के करीब डेढ़ हजार मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए।



दिल्ली में पहली बार लगाई गई मां यमुना की प्रतिमा...

नईदिली (एजेंसी)। दिल्ली में पहली बार मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की गई है। रिंग रोड पर आईएसबीटी क्षमतारी गेट के पास यमुना नदी के किनारे डीडीए की



ओर से मां यमुना की ये प्रतिमा लगाई गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सरकरे ने सोमवार को यमुना प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की गई है।

म.प्र. जबलपुर में बाइक को टक्कर कराकर पलटी स्कॉर्पियो, 5 की मौत

अनूपपुर (एजेंसी)। अनूपपुर में एक स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर कराकर पलटी खाते हुए निर्माणीयन मकान में घुस गई। गाड़ी इतनी रफ्तार से



पलटते हुए गई की आगे का कांच टूट गया, जिससे निकलकर दो युवक बाहर गिर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत पकड़ हो गई। दोनों अस्पताल में दम तोड़ दिया।

म.प्र. में बैंक से 14 करोड़ का सोना, 5 लाख कैश लूटा

जबलपुर (एजेंसी)। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर खितोला इलाके में हथियारबंद बदामों ने सोमवार सुबह 11 बजे बैंक लूट लिया। नुटोरों ने बैंक कर्मचारियों को कटटा दिखाकर धमकाया। फिर 15 मिनट में 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख 70 हार रुपए नकद लेकर भाग निकले। लूटे गए सोने की अनुमानित कीमत साढ़े 14 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। उत्तिस ने जिले में नाकाबंदी कर दी है। और जबलपुर सहित कटनी, मंडला, डिलोरी पुलिस को अलर्ट किया गया है।

पुणे में भीषण हादसा, दर्शन के लिए जारी गाड़ी खाई में पलटी

7 महिलाओं की मौत

पुणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र में पुणे जिले के खेड़ा तालुका में एक भयानक हादसा हुआ है। कुडेश्वर में दर्शन के लिए जा रही महिलाओं से भरी एक पिकअप गाड़ी करीब 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 25 से 30 लोग घायल हो गए। यह हादसा खेड़ा

तालुका के पश्चिमी इलाके में कुडेश्वर शिव मंदिर के रास्ते में हुआ है। मार्केपर रहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव श्री राजन ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक ली



भोपाल (नप्र)। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने कहा कि विद्यार्थियों को अॉनलाइन परीक्षा की सुविधायें दी जायें। दो परीक्षाओं के बीच में पर्याप्त अंतर रखा जायें। स्कॉलरशिप एवं नियमित विद्यार्थियों की संख्या में बढ़िक के प्रयास किये जायें। विद्यार्थियों को उपर्योगी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाए। जिन विद्यार्थियों की 'अपार' आई-डी-जी, नहीं बनी है, बनवाने के प्रयास किये जाएं। सभी विश्वविद्यालय एक माह में उपाधि अप्लाई कर दें। शासन स्तर पर जानकारी पूर्ण परीक्षण उपरांत भेजी जाए। उच्च शिक्षा से संबंधित बैठक प्रत्येक माह संचालनालय स्तर पर आयोजित की जायें। उच्च शिक्षा के सही क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रेशन उत्तरदायी होंगे। श्री राजन ने सोमवार को मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा ली।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर में पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

औषधि वाटिका विकास के लिए एम.पी. ट्रांसको में पौधारोपण



भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन के विजिती कांगड़ों में चल रहे पौधारोपण अधियान के अंतर्गत, मध्यप्रदेश पार्क ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के नवागांव परिसर में औषधीय पौधारोपण किया गया।

पहले चरण में मुख्य सचिव उच्च शिक्षा की सुविधायें दी जायें। दो परीक्षाओं के बीच में पर्याप्त अंतर रखा जायें। स्कॉलरशिप एवं नियमित विद्यार्थियों की संख्या में बढ़िक के प्रयास किये जायें। विद्यार्थियों को उपर्योगी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाए। जिन विद्यार्थियों की 'अपार' आई-डी-जी, नहीं बनी है, बनवाने के प्रयास किये जाएं। सभी विश्वविद्यालय एक माह में उपाधि अप्लाई कर दें। शासन स्तर पर जानकारी पूर्ण परीक्षण उपरांत भेजी जाए। उच्च शिक्षा से संबंधित बैठक प्रत्येक माह संचालनालय स्तर पर आयोजित की जायें। उच्च शिक्षा के सही क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रेशन उत्तरदायी होंगे। श्री राजन ने सोमवार को मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा ली।

'युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी'

पुतिन-ट्रांप की बैठक से पहले जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी ने आज युक्तन के राष्ट्रपति वैलोदीवर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युक्तन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार प्राप्त मोदी से सांख्यिकीय की बात की जायेगी। रूस-युक्तन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति जेलेंस्की ने भारत का आभार जताया। संघर्ष को खत्त करने के संबंध में भारत ने हर संघर्ष सहयोग देने की बात कही है।



बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग प्रभावित

● हिमाचल में 360 से ज्यादा सड़क बंद, उत्तरायण में 1000 लोगों का ऐस्टर्यू

नई दिल्ली/पटना/भोपाल/लाखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश बिहार के कारण बाढ़ के हालात हैं। बिहार के 7 जिले बाढ़ के चेपर में हैं। 10 लाख लोग प्रभावित हो गए। गंगा समत बिहार की 10 नदियों खाते के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना जिले की 24 पचास भी बाढ़ से घिरे हैं।



उत्तर प्रदेश में भी गंगा बारिश से नदियाँ-नाले उफान पर हैं। मुरादाबाद में रामगंगा न

